Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2016 = 4.44, www.srjis.com
UGC Approved Sr. No.48612, OCT- NOV 2017, VOL- 4/24
https://doi.org/10.21922/srjhsel.v4i24.10328

भारत में आदिवासियों की शैक्षिक स्थिति एवं शिक्षक की भूमिका

प्रशांत भगत[1] & गोपाल कृष्ण ठाकुर[2]

[1]पी एच डी शोधार्थी (शिक्षाशास्त्र) म. गां. अं.हिं. वि. वि., वर्धा-442001(महाराष्ट्र)

[2]शिक्षा विभाग , म. गां. अं.हिं. वि. वि., वर्धा-442001(महाराष्ट्र)

Abstract

यह शोध आलेख देश के आदिवासी बच्चों की शैक्षिक स्थिति की चर्चा करते हुए उनके उत्थान के लिए शिक्षकों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयत्न करता है. स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्ष बीत जाने बावजूद आदिवासी समुदाय अभि भी विकास की मुख्यधारा से अलग-थलग दिखाई देता है. सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर उनके विकास के लिए किये जाने वाले अनेकानेक प्रयत्नों के बावजूद उनकी स्थिति में विशेष सुधार नहीं हो पाया है एवं आदिवासियों की अधिकाँश आबादी अभी भी विकास का मुंह नहीं देख पाई है. विकास के एक मुख्य मापदंड के रूप में शिक्षा के महत्त्व को देखते हुए यह आवश्यक है आदिवासियों की शिक्षा की व्यवस्था किस रूप में हो रही है – इस पर ध्यान दिया जाए एवं निष्पक्ष आकलन किया जाए. प्रस्तुत आलेख आदिवासी बच्चों की प्राथमिक, माध्यमिक, एवं उच्च शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करते हुए विषय-वस्तु विश्लेषण के माध्यम से एवं द्वितीयक आंकड़े के रूप में प्राप्त राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त रिपोर्टों आदि में वर्णित तथ्यों के आधार पर उनके शैक्षिक स्तर की अद्यतन स्थिति का उल्लेख करता है. साथ ही महाराष्ट्र राज्य के विशेष संदर्भ में आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए किये जाने प्रयासों की चर्चा करता है. इस आलेख के माध्यम से इस बात पर बल देने की चेष्टा की गई है कि विद्यालयी परिवेश में शिक्षकों की संस्कृति बुद्धिमत्ता के समुचित उपयोग सहित समाज के सभी हितधारकों द्वारा आदिवासी समुदाय के विकास हेतु उनकी शैक्षिक प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाने के लिए अपेक्षित प्रयत्न करने की आवश्यकता है. तभी हमारा समाज एवं देश अपनी समग्रता एवं अनेकता में एकता की अवधारणा को सही मायने में चरितार्थ कर सकेगा.

प्रमुख प्रत्यय/शब्दावली: साक्षरता, सकल नामांकन अनुपात, प्रतिधारण दर, ड्रॉप आउट दर

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के विकास का एक अति महत्वपूर्ण मापदंड है. शैक्षिक प्रक्रिया एवं परिणाम की गुणवत्ता से व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के स्थानीय व वैश्विक निर्देशांक तथा सूचकांक का पता चलता है. समाज की प्रगति का आकलन उसके सदस्यों की शैक्षिक स्थिति से किया जाता है और निस्संदेह शिक्षा व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वैश्विक परिवेश में गुणात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. परन्तु यह भी आवश्यक है कि शैक्षिक विकास का आकलन समाज के प्रत्येक तबके की शैक्षिक स्थिति के समावेशित आकलन के द्वारा परिलक्षित हो. विविध सामाजिक-सांस्कृतिक बहुलता व विशिष्टता से युक्त भारत में अन्य सामाजिक वर्गों के साथ-साथ आदिवासियों की एक विशिष्ट पहचान रही है. भारतीय स्वाधीनता संग्राम में आदिवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका इतिहास में दर्ज है. समाज के विभिन्न वर्गों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए बिरसा मुंडा सहित अनेकों आदिवासियों ने देश को स्वतंत्र कराने में सशक्त भूमिका निभाई है. ऐसी स्थिति में यह देखना अत्यंत आवश्यक है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्षों के बाद वर्तमान समय में आदिवासियों की स्थिति, विशेषतः शैक्षिक स्थिति क्या है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 (25) अनुसूचित जनजातियों का संदर्भ उन समुदायों के रूप में करता है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित किया गया है. संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार, अनुसूचित जनजातियाँ वे आदिवासी या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासियों और आदिवासी समुदायों का भाग या उनके समूह हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है . वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी देश के कुल आबादी का 8.6% हैं और देश के क्षेत्रफल के 15% भाग पर निवास करते है. इनकी आबादी वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार 10.45 करोड़ थी. आदिवासी या अनुसूचित जनजाति की आबादी देश भर में, मुख्यतया वनों और पहाड़ी इलाकों में फैली हुई हैं. इन समुदायों की मुख्य विशेषताएं हैं: आदिम लक्षण, भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट संस्कृति, बाहरी समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच एवं आर्थिक रूप से पिछडापन. पिछली जनगणना के आंकड़े दर्शाते हैं कि अनुसूचित जनजाति आबादियों का 42.02% मुख्यव रूप से कामगार थे जिनमें से 54.50 प्रतिशत किसान और 32.69 प्रतिशत कृषि श्रमिक थे . इस तरह, इन समुदायों में से करीब 87% कामगार प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों में लगे थे.

साक्षरता

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की 59 प्रतिशत है जिसमें आदिवासी पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत 68.5 तथा आदिवासी महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 49.4 है. आगे दी गई तालिका -1 में राष्ट्रीय साक्षरता दर के सापेक्ष आदिवासियों की साक्षरता दर को दर्शाया गया है. उपलब्ध आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि आदिवासियों की सकल साक्षरता दर वर्ष 2001 के 47.1 प्रतिशत से वर्ष 2011 में 59 प्रतिशत हुई है जो कि सकारात्मक वृद्धि का सूचक है. वहीँ जहां आदिवासी पुरुषों की साक्षरता 2001 के 59.2 प्रतिशत से 2011 में 68.5 प्रतिशत हुई है, आदिवासी महिलाओं की साक्षरता उसी अवधि में 34.8 प्रतिशत से 49.4 प्रतिशत हुई है. साथ ही पूरे देश की समस्त जनसँख्या की साक्षरता उसी अवधि में 64.8 प्रतिशत से 73 प्रतिशत हुई है. अर्थात अभी भी देश की समग्र साक्षरता दर की तुलना में आदिवासियों की साक्षरता दर 14 प्रतिशत कम है.

तालिका – 1: आदिवासियों एवं समस्त जनसँख्या की साक्षरता

वर्ष	आदिवासी / अनुसूचित जनजाति			समस्त जनसँख्या		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
2001	59.17	34.76	47.10	75.26	53.67	64.84
2011	68.50	49.40	59.00	80.90	64.60	73.00

स्रोत: महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, भारत

सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश की आदिवासी जनसँख्या का विभिन्न शैक्षिक स्तर पर विगत पांच वर्षों का सकल नामांकन अनुपात संबंधी विवरण तालिका – 2 एवं तालिका – 3 में वर्णित है.

तालिका-2: आदिवासी बच्चों का सकल नामांकन अनुपात (6 वर्ष से 13 वर्ष उम्र वर्ग)

वर्ष	**प्राथमिक (कक्षा 1 - 5) (6-10 वर्ष उम्र वर्ग)**			**उच्चतर प्राथमिक (कक्षा 6 - 8) (11-13 वर्ष उम्र वर्ग)**			**प्रारंभिक (कक्षा 1 - 8) (6-13 वर्ष उम्र वर्ग)**		
	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
2011-12	117.8	115.6	116.7	76.8	74.1	755	103.0	100.6	101.8
2012-13	115.7	113.5	114.6	86.2	86.5	864	105.1	103.9	104.5
2013-14	114.4	111.9	113.2	90.5	92.2	913	105.9	105.0	105.5
2014-15	110.6	108.2	109.4	93.0	95.2	941	104.4	103.7	104.0

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

2015-16	107.8	105.6	106.7	95.4	98.2	967	103.4	103.1	103.2

स्रोत: U-DISE, NUEPA, MHRD

तालिका-3: आदिवासी बच्चों का सकल नामांकन अनुपात (14 वर्ष से 23 वर्ष उम्र वर्ग)

वर्ष	**माध्यमिक (कक्षा 9 - 10) (14-15 वर्ष उम्र वर्ग)**			**उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 11-12) (16-17 वर्ष उम्र वर्ग)**			**उच्च शिक्षा (18-23 वर्ष उम्र वर्ग)**		
	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
2011-12	56.7	50.6	53.8	35.4	29.0	32.3	12.4	9.7	11.0
2012-13	62.6	61.2	61.9	32.3	29.0	30.7	12.4	9.8	11.1
2013-14	70.3	70.1	70.2	36.7	34.1	35.4	12.5	10.2	11.3
2014-15	71.8	72.6	72.2	39.8	37.8	38.8	15.2	12.3	13.7
2015-16	73.7	75.4	74.5	43.8	42.4	43.1	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

स्रोत: U-DISE, NUEPA, MHRD

उपर्युक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभी कक्षा के आदिवासी बच्चों के सकल नामांकन अनुपात में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कमी आई है. परन्तु माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में आदिवासी छात्रों के सकल नामांकन अनुपात में पिछले वर्षों की तुलना में आंशिक बढ़ोतरी हुई है. यद्यपि देश के समस्त छात्र वर्गों के सकल नामांकन अनुपात के परिप्रेक्ष्य में आदिवासी छात्रों के नामांकन में और सुधार की आवश्यकता है. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के आंकड़ों के अनुसार आदिवासी छात्रों का समस्त छात्रों की तुलना में नामांकन, सकल नामांकन दर, प्रतिधारण दर एवं वार्षिक ड्रॉप आउट दर का विवरण तालिका – 4 में उल्लिखित है.

तालिकाप्रतिधारण एवं ड्रॉप आउट दर ,सकल नामांकन ,आदिवासी बच्चों का नामांकन :4-

	अनुसूचित जनजाति की जनसँख्या का प्रतिशत .8.6 – (2011-जनगणना)	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	माध्यमिक विद्यालय	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
1.	कुल नामांकन की तुलना में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों का नामांकन प्रतिशत (16-2015)	10.64	9.81	8.49	6.77
2.	औसत वार्षिक ड्रॉप आउट दर – 15-2014	6.93	8.59	24.68	अनुपलब्ध
3.	प्रतिधारण दर (16-2015)	70.88	50.68 (प्रारंभिक स्तर)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
4.	सकल नामांकन अनुपात)Gross Enrolment Ratio-2015) - ((16	106.74	96.71	74.53	43.12

स्रोत16-2015 ,APEUN ,ESID-U :

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

उपर्युक्त तालिका – 4 में उल्लिखित आंकड़ों से प्रतीत होता है कि जहाँ प्राथमिक स्तर पर आदिवासी बच्चों का नामांकन प्रतिशत 10.64 है, वहीँ उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नामांकन प्रतिशत उत्तरोत्तर कम होता गया है. साथ ही माध्यमिक स्तर पर वार्षिक ड्रॉप आउट दर प्राथमिक एवं उच्च-प्राथमिक स्तर की तुलना में अत्यधिक है. यह चिंता का विषय है. उसी प्रकार माध्यमिक स्तर पर आदिवासी छात्रों के वार्षिक प्रतिधारण दर एवं सकल नामांकन अनुपात में सुधार की आवश्यकता है अन्यथा शैक्षिक स्तर पर व्याप्त असमानता बढती चली जाएगी. इस असमानता का एक परिणाम उच्च शिक्षा में आदिवासी छात्रों का प्रतिनिधित्व असंगत रूप से कम है जिसका प्रभाव गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जनजातियों/आदिवासियों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक होने के रूप में परिलक्षित होता है. आदिवासी बच्चों की शैक्षिक स्थिति में मात्रात्मक सुधार के साथ-साथ गुणात्मक सुधार की अत्यंत आवश्यकता है जिससे कि ये बच्चे मुख्यधारा में शामिल होकर सम्मानजनक रूप से अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकें एवं समाज एवं देश के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें. इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालयों एवं विभिन्न स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में इनके लिए समावेशी वातावरण का निर्माण हो सके. शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन यथोचित रूप में कर सकें एवं इन बच्चों का अध्ययन-अनुभव सहज, सरल एवं आनंददायक हो सके. ऐसे में शिक्षकों की भूमिका एवं संवेदनशीलता पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है.

महाराष्ट्र में आदिवासियों की शैक्षिक स्थिति

प्रस्तुत आलेख का विमर्श मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य के आदिवासियोंकी शैक्षिक स्थिति पर केन्द्रित है. महाराष्ट्र राज्य के कुल क्षेत्रफल में से 5466 वर्ग कि .मी. क्षेत्र में आदिवासी आबादी निवास करती हैं. महाराष्ट्र राज्य में आदिवासी विकास के लिये एक स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित है. इस मंत्रालय द्वारा आदिवासी समूह के लिये विविध विकासात्मक योजनाओं का संचालन व नियंत्रण होता है. इन योजनाओं में कृषि, आवास, वित्तीय सहायता एवं शिक्षा प्रमुख है. इस मंत्रालय द्वारा आदिवासी बहुल क्षेत्रों को चार भागों में विभाजित किया है – (1) ठाणे (2) नासिक (3)अमरावती एवं (4)नागपुर. इन चार क्षेत्र निकायों के बेहतर व्यवस्थापन हेतु आदिवासी आयुक्तालय की स्थापना की गयी है . अपर आदिवासी आयुक्त इसका प्रमुख अधिकारी होता है . इन चार जिलों के मुख्यालयों में स्थापित आदिवासी विकास आयुक्तालय द्वारा आदिवासी आश्रम स्कूलों का परिचालन होता है. आदिवासी आश्रम स्कूलों के दो भाग है – (1) सरकारी आश्रम स्कूल – जो सम्पूर्णत:आदिवासी विकास आयुक्तालय द्वारा संचालित होते हैं, एवं (2) अनुदानित आश्रम स्कूल – जो सरकारी अनुदान से सार्वजनिक ट्रस्ट या शैक्षिक संस्था द्वारा संचालित होते हैं. राज्य के आदिवासियों की शैक्षिक स्थिति में देश के एनी भागों के आदिवासियों की तुलना में कोई विशेष सुधार दृष्टिगोचर नहीं होता है. तालिका – 5 में राज्य के आदिवासियों की शैक्षिक स्थिति का उल्लेख किया गया है.

तालिका – 5: महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक स्थिति

क्र.	आदिवासी उप-वर्ग	वगैर शैक्षिक स्तर के साक्षरता दर	प्राथमिक स्तर से नीचे	प्राथमिक स्तर	उच्च-प्राथमिक स्तर	माध्यमिक स्तर	तकनीकी / गैरतकनीकी	स्नातक स्तर
1	समस्त आदिवासी	3.3	41.7	25.7	15.6	13.4	0.2	2.1
2	भील	7.0	49.9	23.5	8.6	9.7	0.1	1.3
3	गोंड	2.0	40.3	26.2	16.9	13.0	0.1	1.4
4	कोलिमहादेव	2.4	35.3	28.2	15.2	15.9	0.3	2.6
5	वरली	3.6	52.7	26.8	10.1	6.0	0.1	0.7
6	कोकना	2.9	38.9	26.1	13.1	16.3	0.4	2.5

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

7	ठाकुर	2.9	43.8	25.8	12.4	12.2	0.3	2.6

स्रोत: आदिवासी विकास मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य

आदिवासी आश्रम विद्यालयों के शिक्षकों की पृष्ठभूमि

सरकार द्वारा संचालित आदिवासी आश्रम विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का चयन आदिवासी विकास आयुकतालय द्वारा होता है. इन विद्यालयों में शिक्षकों का चयन एक स्पर्धा परीक्षा पास करने के उपरांत मौखिक अभिव्यक्ति के अंको के आ धार पर गुणवत्तापूर्वक किया जाता है. इसमें सं वैधानिक व्यवस्थानुसार आरक्षण नियमों का पालन किया जाता है. शिक्षक के लिये जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता चाहिए वही योग्यता इन शिक्ष कों के लिए अनिवार्य होती है. आदिवासी आश्रम विद्यालय सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में तथा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्थित होते हैं और ये आवासीय विद्यालय के रूप में स्थापित होते हैं. विद्यालय में प्रवेशित छात्रों के रहने व खाने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही होती है और शिक्षकों को भी विद्यार्थियों के साथ 24 घंटे रहना होता है. महाराष्ट्र के आदिवासी विद्यालयों में सामान्यतया अधिकाँश शिक्षक गैर आदिवासी होते हैं और इस तरह छात्रों के सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश से भिन्न परिवेश के होते हैं. ऐसे में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इन विद्यालयों के शिक्षक सम्पूर्ण संवेदनशीलता के साथ आदिवासी बच्चों के शैक्षिक, संज्ञानात्मक एवं सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए उनके समुचित शैक्षिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण कर सकें जिससे शैक्षिक प्रक्रिया की सार्थकता सिद्ध हो सके. इस हेतु गैर आदिवासी पृष्ठभूमि के उन शिक्षकों की सामजिक व सांस्कृतिक बुद्धिमत्ता के अवबोधन का अध्ययन करना एवं यह जानना समीचीन प्रतीत होता है कि किस प्रकार ये शिक्षक ऐसे विद्यालय विशेष में अपनी सांस्कृतिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा का स्पष्ट अवबोधन कर पाते हैं और तत्संबंधी व्यवहार कौशल का उपयोग आदिवासी बच्चों के विद्यालयी अनुभवों को समृद्ध करने में कर पाते हैं. यह भी जानना आवश्यक प्रतीत होता है कि गैर आदिवासी शिक्षक द्वारा आदिवासी छात्रों के शैक्षिक अनुभव को संपुष्ट करने हेतु किस प्रकार के क्रियाकलाप किये जाते है एवं उन छात्रों की शैक्षिक स्थिति पर इन समस्त उपक्रमों का क्या प्रभाव पड़ता है.

उपसंहार

भारतीय समाज की मूल मान्यताओं में श्रीमद भगवदगीता के इन प्रसिद्ध वचन - 'सा विद्या या विमुक्तये' और 'न ही ज्ञानेन सदृश्य पवित्र महि विद्यते' अर्थात 'विद्या ही मनुष्यत्व के सम्पूर्ण विकास का माध्यम है' निहित है. जो कि बिना किसी भेद-भाव के समस्त मनुष्यों के लिए निर्धारित की गई है. परन्तु अभी भी अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में आदिवासियों की वर्तमान शैक्षिक स्थिति संतोषजनक नहीं है. हमें आंकड़े यही बताते हैं कि उच्च शिक्षा में आदिवासी विद्यार्थियों की स्थिति चिंताजनक है . उनका स्कूल पलायन (School Drop Out) का प्रमाण अन्य सामजिक वर्ग के बालकों की तुलना में अधिक है जो कि चिंता का विषय है. एक प्रगतिशील समाज व राष्ट्र के लिए यह चित्र निःसंदेह अच्छा नही है . अनुदानित व सरकारी आश्रम स्कूल की व्यवस्था निःशुल्क छात्रावास, निःशुल्क भोजन, तथा निःशुल्क शैक्षिक अध्ययन सामग्री तथा गणवेश की प्रतिपूर्ति सरकार करती है. इतनी सारी व्यवस्था होने के बाव जूद इसका अपेक्षित परिणाम आदिवासी शिक्षा नहीं दिख रहा है. यह गहन विचार का विषय है. समाज के सभी हितधारकों के लिए यह आवश्यक है कि इस पर गंभीर विमर्श करते हुए समाज के इस वर्ग के अस्तित्व की महत्ता को उचित स्थान दें एवं उनके शैक्षिक-सामाजिक-सांकृतिक विकास के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाएं.

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

आहूजा आर एंड एम (2008).समाजशास्त्र –विवेचना एवं परिपेक्ष्य .जयपुर :रावत पब्लिकेशन

आहूजा आर(2007).भारतीय समाज .जयपुर :रावत पब्लिकेशन

अरोरा पल्लवी . *(2012) . Cultural Intelligence and the Customer saticfactoin: A Case Studying five star hotels.* (अप्रकाशित).पी एच डी शोध प्रबंध . प्रबंधन विभाग.जम्मू विश्वविध्यालय.जम्मू

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

डेविट पी . (2013). *Cultural intelligianceand the expartriate teacher:A Study of expartriate teacher's constructs of themselves as culturally intelligent.*(अप्रकाशित).पी एच डी .शोध प्रबंध. शिक्षा विभाग.एक्सेटर विश्वविद्यालय.

जोसेफ त्से. (1998). *An ethnographic study ofteacher's job satisfaction and organizational commitments in selected Newzeland secondary schools.*(अप्रकाशित).शोध प्रबंध .पी एच डी . शिक्षा विभाग. Massy विश्वविद्यालय .न्यूजीलैंड

हट बेथ . (2012).*Smartness as a cultural practice in schools.American educational research journal.49,438-460*

हॉपनर,वांग ,झहू.(2014). *Cultural intelligence(CQ)Trajectores in neo-international students implications for the devalopement cross cultural compentance. Americn Educational Research Journal.*

कोरदास्तानी डी ,(2006). *A Cross cultural study of acadomic achievement among the Iranian and Indian adolscets in relation to parenting style ,classroom environment,intelligence, and self regulation*.(अप्रकाशित)पी एच डी .शोध प्रबंध .शिक्षा विभाग. पंजाब विश्वविद्यालय.

मिदताला रानी .(2009). *Problems of Tribal Education In India.* नई दिल्ली :कनिष्क प्रकाशन

http://www.firstpost.com/india/literacy-rates-scheduled-tribes-far-national-average-says-parliamentary-panel-2154745.html. Retrieved on 30.11.2017

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies